



वर्ष एक नज़र में



वर्ष एक नज़र में

1. भारत में कोयला भंडार

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सीएमपीडीआई, एमईसीएल, जीएसआई, एससीसीएल और अन्य द्वारा अनुमानित संसाधनों के आधार पर 01.04.2024 तक 1200 मीटर की गहराई तक तैयार की गई भारतीय कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधनों की सूची 389421.34 मि.ट. है। इसके स्रोत मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पाए गए हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार प्रकार-वार और श्रेणी-वार संसाधन

(झिलिंग मि. टन में)

गहराई सीमा (एम)	मापित (331)	निर्दिष्ट (332)	अनुमानित (333)		कुल
			अन्वेषण	मैपिंग	
गोंडवाना कोल					
कोकिंग					
0-300	8695.70	3899.63	36.02		12631.35
0-600	9153.94	87.28	0.00		9241.22
300-600	2611.27	5053.06	737.06		8401.39
600-1200	2603.29	2760.96	1174.68		6538.93
0-1200	23064.20	11800.93	1947.76		36812.89
गैर-कोकिंग					
0-300	131810.33	53840.06	6535.09		192185.48
0-600	6075.22	66.65	29.63		6171.50
300-600	43759.78	62153.77	13118.01		119031.56
600-1200	6897.22	20733.81	5926.60		33557.63
0-1200	188542.55	136794.29	25609.33		350946.17
तृतीयक कोयला					
हाई सल्फर					
0-300	414.56	105.16	190.64	749.92	1460.28
300-600	185.85	16.15	0.00	0.00	202.00
0-600	600.41	121.31	190.64	749.92	1662.28
कुल	212207.16	148716.53	27747.73	749.92	389421.34

नोट आंकड़े अनंतिम हैं।



01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, गहराई-वार और श्रेणी-वार संसाधन

(संसाधन मिलियन टन में)

गहराई रेंज (मी.)	कोकिंग			गैर-कोकिंग			हाई सल्फर	कुल योग
	प्राइम	मध्यम	सेमी कोकिंग	सुपीरियर (जी1-जी6)	निर्दिष्ट (जी7-जी17)	अन्यो डेड		
0-300	2.21	12162.37	466.77	21623.72	164026.67	6535.09	1460.28	206277.11
0-600	4596.55	4644.67	0.00	449.38	5692.49	29.63	0.00	15412.72
300-600	0.34	7552.95	848.10	13913.54	92000.01	13118.01	202.00	127634.95
600-1200	844.31	5212.01	482.61	3885.19	23745.84	5926.60	0.00	40096.56
0-1200	5443.41	29572	1797.48	39871.83	285465.01	25609.33	1662.28	389421.34

राज्य-वार कोयला संसाधन-

(कोयला संसाधन मिलियन टन में)

राज्य	मापित (331)	निर्दिष्ट (332)	अनुमानित (333)	संसाधन
ओडिशा	53799.43	39053.01	6351.39	99203.83
झारखंड	59876.88	27135.39	4799.30	91811.57
छत्तीसगढ़	40078.14	41092.78	1495.44	82666.36
पश्चिम बंगाल	18752.19	11432.59	3773.29	33958.07
मध्य प्रदेश	15425.17	12378.97	5010.99	32815.13
तेलंगाना	11256.78	8496.57	3452.17	23205.52
महाराष्ट्र	8163.11	3371.82	1816.70	13351.63
बिहार	2346.36	3014.65	36.66	5397.67
आंध्र प्रदेश	1024.65	2368.94	778.17	4171.76
उत्तर प्रदेश	884.04	177.76	0.00	1061.80
मेघालय	95.64	16.65	470.93	583.22
असम	464.78	57.21	3.02	525.01
नागालैंड	8.76	21.83	447.72	478.31
सिक्किम	0.00	58.25	42.98	101.23
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	18.89	90.23
कुल	212207.16	148716.53	28497.65	389421.34

2. भारत में लिग्नाइट संसाधन

देश में लिग्नाइट भंडार लगभग 47295.61 मिलियन टन (01.04.2024 तक) अनुमानित है। प्रमुख भंडार तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, इसके बाद राजस्थान, गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल हैं।



राज्यवार लिग्नाइट संसाधन—

(लिग्नाइट संसाधन मिलियन टन में)

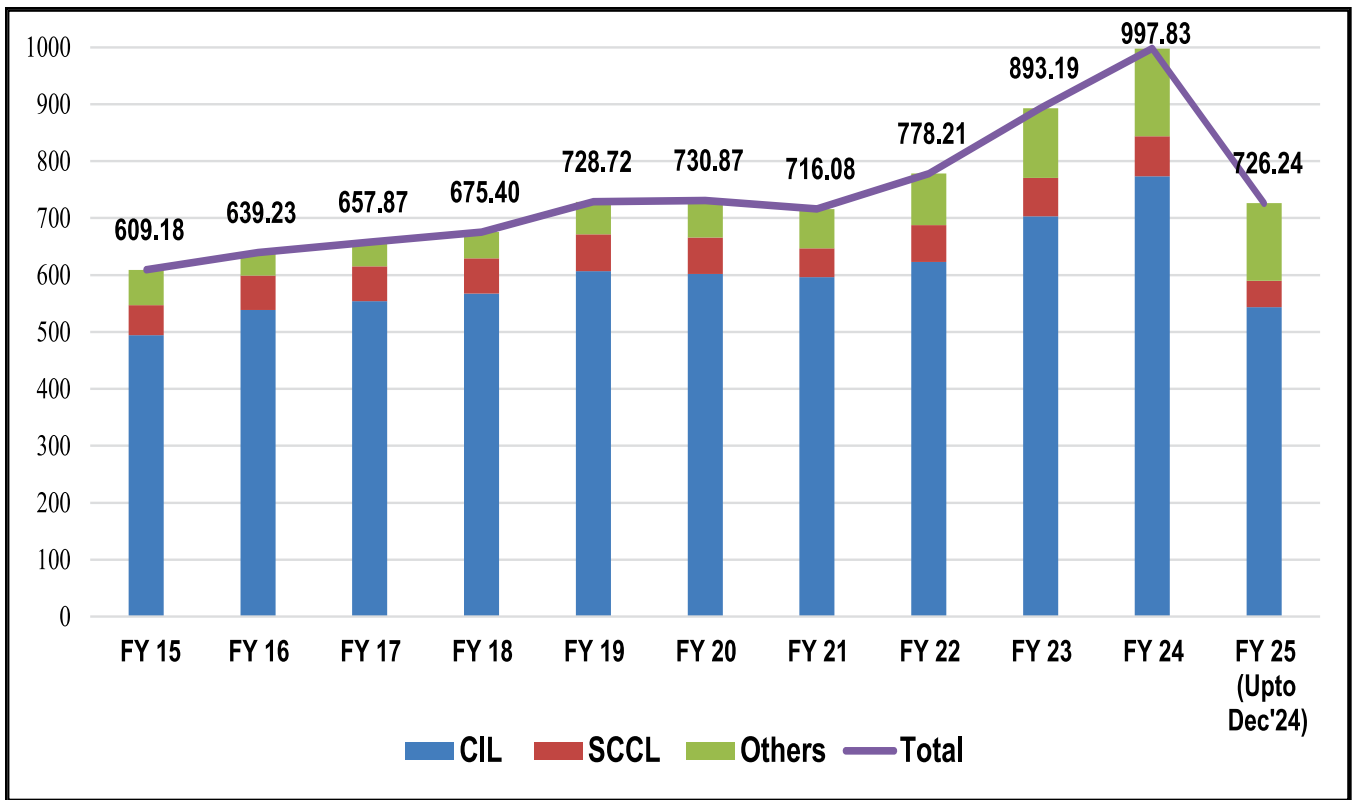
राज्य	मापित (331)	निर्दिष्ट (332)	अनुमानित (333)	संसाधन
पांडिचेरी	0.00	405.61	11.00	416.61
तमिलनाडु	5476.00	21412.16	10635.49	37523.65
राजस्थान	1203.85	3108.55	2273.84	6586.24
गुजरात	1278.65	283.70	1159.70	2722.05
जम्मू और कश्मीर	0.00	20.25	7.30	27.55
केरल	0.00	0.00	9.65	9.65
पश्चिम बंगाल	0.00	1.13	2.80	3.93
ओडिशा	5.93	0.00	0.00	5.93
कुल	7964.43	25231.40	14099.78	47295.61

3. कोयला उत्पादन

2023–24 के दौरान, कच्चे कोयले का वास्तविक उत्पादन 997.83 मिलियन टन (मि.ट.) है, जबकि वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 1012.34 मि.ट. है। सीआईएल, एससीसीएल तथा अन्य से कोयला उत्पादन का कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है

कंपनीवार कोयला उत्पादन									
[मिलियन टन (मि.ट.) में]									
कंपनी	2022–23	2023–24		उपलब्धि (%)	वृद्धि	(24 दिसंबर तक)			अनुमानित उत्पादन (जनवरी–मार्च, 25)
	वास्तविक	वार्षिक लक्ष्य	वास्तविक			वार्षिक लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि (%)	
सीआईएल	703.20	780.20	773.65	99.16%	▲ 10.02%	575.42	543.36	94.43%	294.84
एससीसीएल	67.14	70.00	70.02	100.03%	▲ 4.29%	51.23	46.76	91.27%	25.24
कैस्टिव व अन्य	122.85	162.14	154.16	95.08%	▲ 25.49%	124.62	136.12	109.23%	33.88
कुल	893.19	1012.34	997.83	98.57%	▲ 11.72%	751.27	726.24	96.67%	353.96



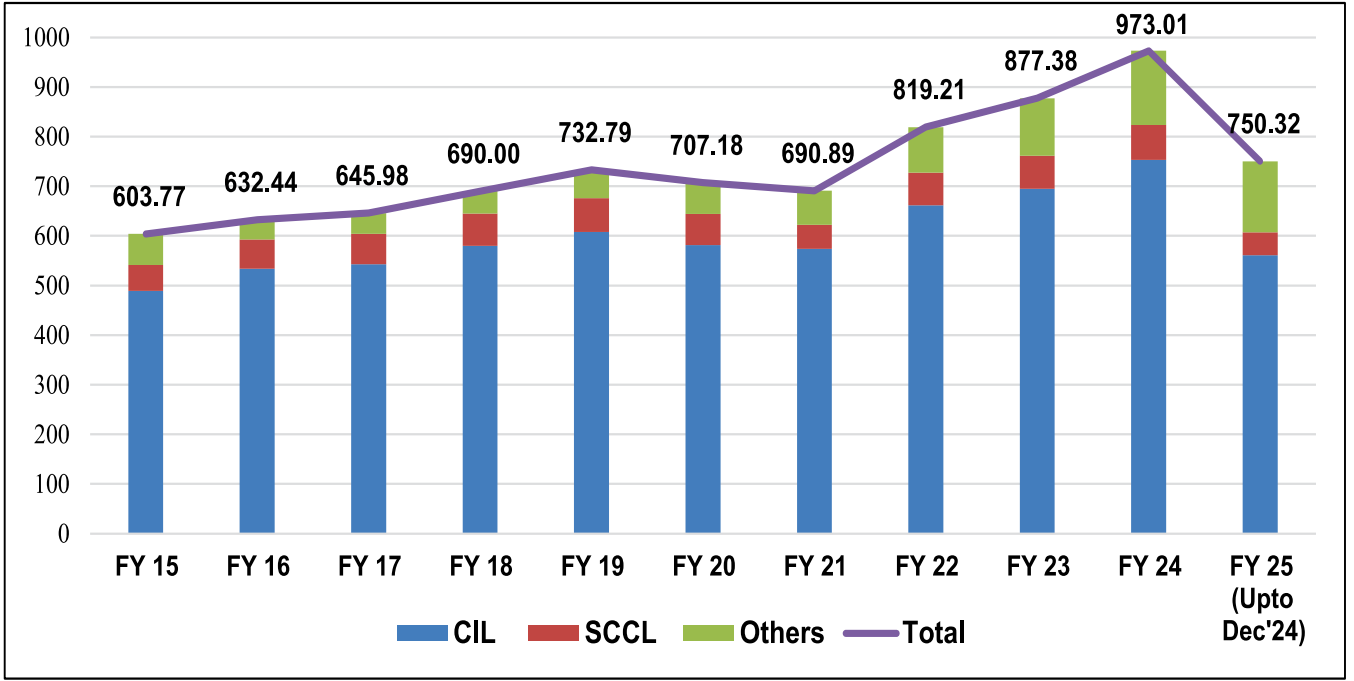


4. कोयला प्रेषण

2023-24 के दौरान, 1012.14 मि.ट. के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक कच्चा कोयला 973.01 मि.ट. है। सीआईएल, एससीसीएल तथा अन्य से कोयला प्रेषण का कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनीवार कोयला प्रेषण									
[मिलियन टन (मि.ट.) में]									
कंपनी	2022-23	2023-24		उपलब्धि (%)	वृद्धि	(24 दिसंबर तक)			अनुमानित प्रेषण (जनवरी-मार्च, 25)
	वास्तविक	वार्षिक लक्ष्य	वास्तविक			वार्षिक लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि (%)	
सीआईएल	692.22	780.00	753.54	96.58%	▲ 8.46%	618.37	560.63	90.66%	278.19
एससीसीएल	66.69	70.00	69.86	99.80%	▲ 4.75%	51.23	46.19	90.16%	25.81
कैप्टिव व अन्य	118.46	162.14	149.81	92.40%	▲ 29.00%	124.62	143.51	115.16%	26.49
कुल	877.37	1012.14	973.01	96.13%	▲ 10.90%	794.22	750.32	94.47%	330.50





5. कंपनी-वार कच्चा कोयला प्रेषण:

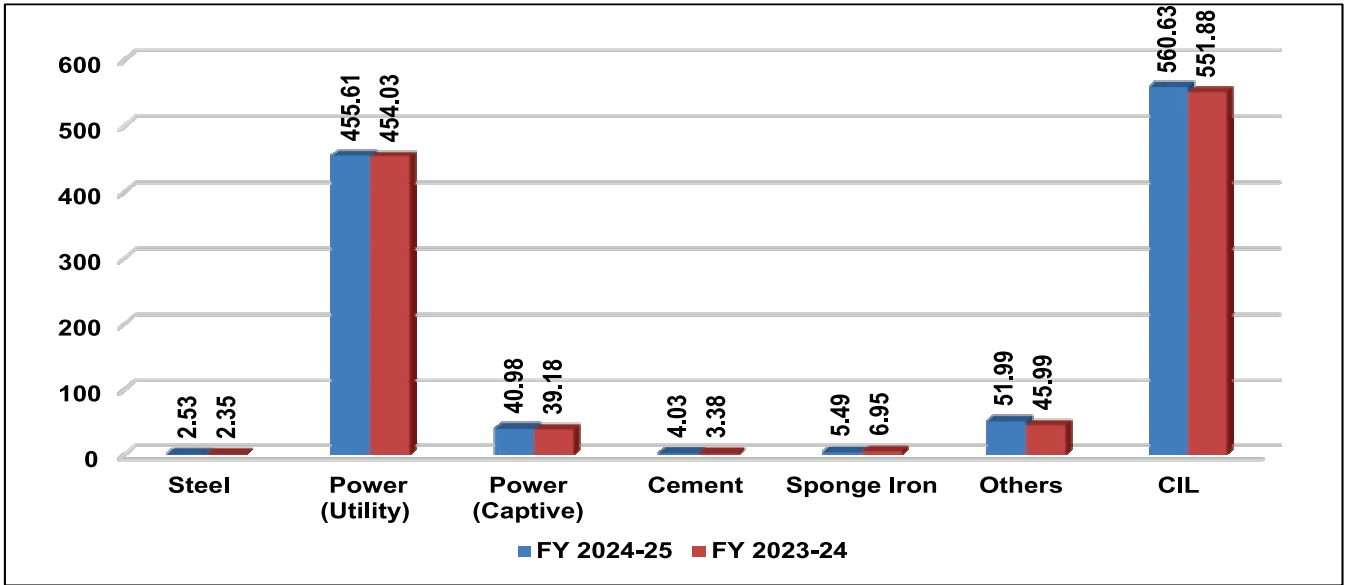
(मि.ट. में)

कंपनी	वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिसंबर 24, तक)			वित्तीय वर्ष 2023-24	% वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	% उपलब्धि	वास्तविक	
सीआईएल	618.37	560.63	90.66%	753.54	▲ 1.58%
एससीसीएल	51.23	46.19	90.16%	69.86	▼ 9.49%

6. क्षेत्रवार कच्चा कोयला प्रेषण-सीआईएल (अनंतिम)

(मि.ट. में)

क्षेत्र	दिसंबर तक		: वृद्धि
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	
इस्पात	2.53	2.35	▲ 7.66%
विद्युत (उपयोगिता)	455.61	454.03	▲ 0.35%
विद्युत (कैप्टिव)	40.98	39.18	▲ 4.59%
सीमेंट	4.03	3.38	▲ 19.23%
स्पंज आयरन	5.49	6.95	▼ 21.01%
अन्य	51.99	45.99	▲ 13.03%
सीआईएल	560.63	551.88	▲ 1.58%

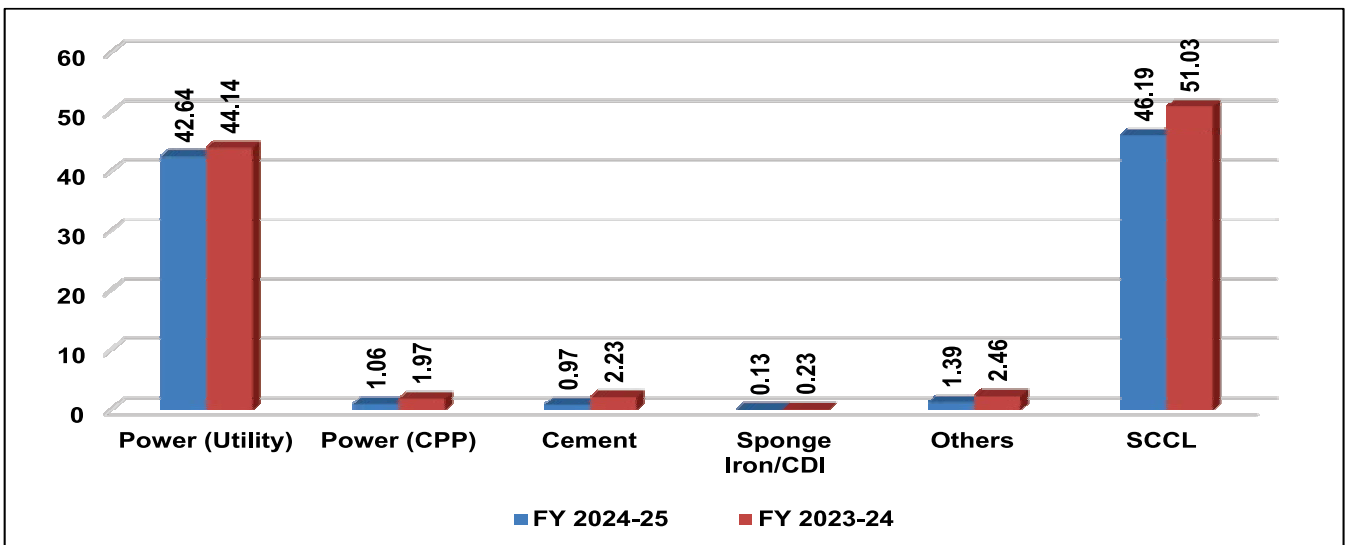


सीआईएल की क्षेत्र-वार कोयला प्रेषण स्थिति

7. एससीसीएल का क्षेत्र-वार प्रेषण

(मि.ट. में)

क्षेत्र	दिसंबर तक		वृद्धि (%)
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	
विद्युत (उपयोगिता)	42.64	44.14	▲ 3.40%
विद्युत (सीपीपी)	1.06	1.97	▼ 46.19%
सीमेंट	0.97	2.23	▼ 56.50%
स्पंज आयरन/सीडीआई	0.13	0.23	▼ 43.48%
अन्य	1.39	2.46	▼ 43.62%
एससीसीएल	46.19	51.03	▲ 9.49%



एससीसीएल की क्षेत्र-वार कोयला प्रेषण स्थिति



8. लिग्नाइट उत्पादन

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) थर्मल पावर स्टेशनों से जुड़ी ओपनकास्ट लिग्नाइट खानों के साथ एक एकीकृत खनन सह विद्युत कंपनी है। वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2024-25 (दिसंबर, 24 तक) के लिए एनएलसीआईएल और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा लिग्नाइट उत्पादन और बिजली उत्पादन: —

उत्पाद	इकाई	वित्त वर्ष 2024-25 (दिसंबर 24, तक)	
		लक्ष्य	वास्तविक
ओवरबर्डन	मिलियन-मीटर क्यूब (एमएम ³)	127.81	123.56
लिग्नाइट	मि.ट.	19.34	17.14
कोयला	मि.ट.	12.50	11.52
सकल विद्युत (एनएलसीआईएल)	मिलियन यूनिट (एमयू)	20352.67	16178.36
विद्युत निर्यात (एनएलसीआईएल)	एमयू	18275.59	14084.67
सकल विद्युत (एनटीपीएल)	एमयू	5449.00	3992.16
विद्युत निर्यात (एनटीपीएल)	एमयू	5162.00	3693.87

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी वार लिग्नाइट उत्पादन

(मि.ट. में)

कंपनियां	वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिसंबर 24, तक)
एनएलसी	17.15
जीएमडीसीएल	5.83
जीआईपीसीएल	2.11
जीपीसीएल	1.35
आरएसएमएमएल	0.68
जीएचसीएल	0.05
वीएसएलपीपीएल	0.59
बीएलएमसीएल	4.43
अखिल भारत	32.17

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनीवार लिग्नाइट प्रेषण

(मि.ट. में)

कंपनियां	वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिसंबर 24, तक)
एनएलसी	17.57
जीएमडीसीएल	5.83

कंपनियां	वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिसंबर 24, तक)
जीआईपीसीएल	2.11
जीपीसीएल	1.18
आरएसएमएमएल	0.68
जीएचसीएल	0.05
वीएसएलपीपीएल	0.57
बीएलएमसीएल	4.44
अखिल भारत	32.42

9. कोयला लिंकेज नीति का कार्यान्वयन

गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी नीति सीआईएल ने लिंकेज नीलामियों के सात चरण पूरे कर लिए हैं और अब तक 8वां चरण प्रगति पर है, सफल बोलीदाताओं द्वारा कुल 177.64 मिलियन टन की बुकिंग की गई है।

भारत में पारदर्शी रूप से कोयला (कोयला) के दोहन और आवंटन स्कीम (शक्ति) नीति: सीआईएल द्वारा शक्ति नीति के विभिन्न प्रावधानों के तहत 495.72 मिलियन टन कोयला लिंकेज बुक/आवंटन किया गया है।



9.1. नई नीतिगत पहल:

(I) **गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के कोयला लिंकेज की नीलामी के लिए नीति के तहत नया उप-क्षेत्र:** एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत "डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोल का उपयोग करके इस्पात" के नामकरण के साथ एक नया उप-क्षेत्र मार्च 2024 में बनाया गया है, जिससे देश में इस्पात उद्योग में घरेलू कोकिंग कोयले की खपत में वृद्धि होगी।

(II) **शक्ति नीति के पैरा बी (viii) (ए) में संशोधन:** संशोधित पैरा बी (viii) (ए) निम्नानुसार है:

"निजी जनरेटर सहित ऐसे सभी बिजली संयंत्र जिनके पास पीपीए नहीं है, उन्हें शक्ति नीति के तहत 3 महीने की अवधि और अधिकतम 1 वर्ष तक कोयला लिंकेज की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उस लिंकेज के माध्यम से उत्पन्न बिजली पावर एक्सचेंजों में किसी भी उत्पाद के माध्यम से या डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट एनर्जी प्राइस (डीईईपी) पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में बेची जाए। इस संबंध में कोयला मंत्रालय के परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा एक कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी।

9.2. तीसरे पक्ष के नमूने द्वारा कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करना:

कोल इंडिया लि/एससीसीएल द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता के मुद्दे पर सरकार द्वारा उच्चतम महत्व दिया जाता है। कोयले की गुणवत्ता में उपभोक्ताओं (विद्युत उपयोगिताओं) की चिंताओं को दूर करने के लिए, कोयला कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 2015 में कोयले के तीसरे पक्ष के नमूने के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू की गई थी। देश में विभिन्न कोयला लदान स्थलों पर कोयले के नमूनों के संग्रहण, तैयारी, विश्लेषण और प्रलेखन के लिए तृतीय पक्ष नमूना एजेंसियों (टीपीएसए) को पैनल में शामिल किया गया है। तृतीय पक्ष नमूने की प्रगति की समीक्षा कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है।

तृतीय पक्ष नमूनाकरण का विस्तार विभिन्न एफएसए के अंतर्गत कोयला लेने वाले गैर-विद्युत उपभोक्ताओं तक भी किया गया है और वैकल्पिक आधार पर ई-नीलामी की गई है।

टीपीएसए का चयन या तो नामांकन या निविदा की प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। नए टीपीएसए को अब पीएफसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा पैनल में शामिल किया जा रहा है और वर्तमान में कुल बारह टीपीएसए पैनलबद्ध हैं।

इसका उद्देश्य हमारे ग्राहकों को सही गुणवत्ता वाले कोयले की डिलीवरी सुनिश्चित करना है और इसलिए, खनन से लेकर कोयले के प्रेषण तक कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का पालन करना है।

2017-18 से 2024-25 (दिसंबर '24 तक) से सीआईएल की ग्रेड अनुरूपता में सुधार नीचे दिया गया है:

सीआईएल का गुणवत्ता निष्पादन

(मि.ट. में)

वित्तीय वर्ष	अंतिम ग्रेड अनुरूपता (%) में
2017-18	58
2018-19	66
2019-20	65
2020-21	68
2021-22	71
2022-23	75
2023-24	81
2024-25 (दिसंबर 2024 तक)	81

10. मिशन कोकिंग कोल

कोकिंग कोल, जो देश में एक दुर्लभ वस्तु है, का उपयोग मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस रूट के माध्यम से कोक के निर्माण में तत्पश्चात् इस्पात बनाने में उपयोग किया जाता है। घरेलू कोकिंग कोयला अधिक राख वाला कोयला है (अधिकांशत 18% -49% के बीच) और धमन भट्टी में सीधे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। घरेलू कोकिंग कोयले को राख की

प्रतिशतता (<18% राख) को कम करने के लिए धोया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग से पहले आयातित कोकिंग कोल (<9% राख) के साथ मिश्रित किया जाता है। इस्पात क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए देश में कोकिंग कोल उत्पादन और परिष्करण में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है। धुले हुए कोकिंग कोल की बढ़ी हुई आपूर्ति के परिणामस्वरूप देश के आयात में कमी आएगी और देश की विदेशी मुद्रा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

सीआईएल 03 (11.6 एमटीपीए) नवनिर्मित वाशरियों सहित 18.35 एमटीपीए की कुल प्रचालनीय क्षमता वाली 10 कोकिंग कोयला वाशरियों का प्रचालन कर रही है। 2023–24 के दौरान मौजूदा कोकिंग कोल वाशरियों से कुल धुले हुए कोकिंग कोल का उत्पादन लगभग 2.258 मि.ट. था। सीआईएल ने 2029–30 तक 21.5 एमटीपीए की क्षमता के साथ अतिरिक्त 08 कोकिंग कोल वाशरी स्थापित करने की योजना बनाई थी। सीआईएल 04 पुरानी वाशरियों के मुद्रीकरण की प्रक्रिया में भी है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सीआईएल ने 2029–30 तक 15.77 एमटीपीए के कुल धुले हुए कोकिंग कोल उत्पादन को हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

11. राजस्व-साझाकरण पर प्रस्तावित सीआईएल की बंद खानों का अनलॉकिंग मूल्य

कोयला पीएसयू के पास बड़ी संख्या में बंद/परित्यक्त खानें हैं जिनमें उपयुक्त गहराई पर पर्याप्त खनन योग्य भंडार हो सकते हैं, जिन्हें वर्तमान में सुरक्षा कारणों और/अथवा अलाभकारी प्रचालनों के कारण समाप्त कर दिया गया है अथवा बंद कर दिया गया है। कोयला मंत्रालय ने बंद की गई/परित्यक्त खानों के प्रचालन के लिए निजी क्षेत्र के साथ जुड़ने का प्रयास किया ताकि इसकी क्षमता का उपयोग किया जा सके और घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया जा सके।

सीआईएल ने राजस्व हिस्सेदारी मॉडल पर निजी खनन कंपनियों को पेशकश करने के लिए बंद की गई 34 खानों की पहचान की। इनमें से 24 बंद की गई खानों को प्रचालन के लिए सौंप दिया गया है, 3 खानें निविदा चरण में हैं और 7

खानों के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की जानी है।

12. खनन को पुनर्जीवित करना: एमडीओ के माध्यम से सार्वजनिक-निजी सहयोग

घरेलू कोयला उत्पादन में तेजी लाने तथा कोयला आयात निर्भरता को कम करने के लिए पारदर्शी वैश्रिवक खुली निविदाओं के माध्यम से कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला पीएसयूज द्वारा खान विकासकर्ता सह प्रचालकों (एमडीओ) की नियुक्ति की जाती है। एमडीओ से प्रौद्योगिकी में वृद्धि, आर्थिक रूप से व्यवहार्य संचालन और उत्पादन में वृद्धि एक साथ होंगे।

सीआईएल ने एमडीओ पद्धति के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 253 एमटीपीए की अनुमानित कोयला उत्पादन क्षमता वाली 28 परियोजनाओं की पहचान की है। निजी क्षेत्र के साथ इस साझेदारी से कोयला क्षेत्र में निवेश आएगा। पहचान की गई परियोजनाओं में से 14 परियोजनाएं एमडीओ को सौंपी गई हैं। 14 परियोजनाओं में से 68 एमटीपीए की क्षमता वाली 6 परियोजनाओं ने उत्पादन शुरू कर दिया है।

13. फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स

कोयला मंत्रालय ने खानों से कोयले के सड़क परिवहन को समाप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण तैयार किया है और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के अंतर्गत यंत्रिकृत कोयला परिवहन और लोडिंग सिस्टम के उन्नयन के लिए कदम उठाए हैं।

रैपिड लोडिंग सिस्टम वाले कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) और साइलो कोयला क्रशिंग, साइजिंग और तेजी से कंप्यूटर-एडेड लोडिंग जैसे लाभ प्रदान करते हैं। कम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ, सटीक पूर्व-तौल मात्रा और बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले को लोड किया जा सकता है। बेहतर लदान समय वैगन की सुस्ती को कम करेगा जिससे उनकी उपलब्धता में वृद्धि होगी। सड़क नेटवर्क पर भार को कम करने से स्वच्छ पर्यावरण और डीजल पर बचत को बढ़ावा मिलता है। यह कंपनी, रेलवे और उपभोक्ताओं के लिए चौतरफा जीत की स्थिति होगी।



सीआईएल ने कोयले के मशीनीकृत लोडिंग के लिए कुल 94 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं की योजना बनाई है। अगस्त 2019 से पहले 151 एमटीवाई क्षमता वाली 20 परियोजनाएं स्थापित की गई थीं। अगस्त 2019 के बाद 837.5 एमटीवाई क्षमता वाली 74 परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी। इनमें से 17 परियोजनाएं आज की तारीख तक चालू हो चुकी हैं, 24 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 31 परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।



कुसमुंडा एफएमसी

इस प्रकार, आज तक, 37 एफएमसी परियोजनाएं चालू की गई हैं और शेष परियोजनाएं वित्त वर्ष 2028-29 तक चालू हो जाएंगी

एससीसीएल ने 34.50 मि.ट. की क्षमता के साथ 5 एफएमसी परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बनाई। 5 एफएमसी परियोजनाओं में से, 13.50 एमटीपीए क्षमता के साथ दो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 21 एमटीपीए की क्षमता वाली 3 परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं।

इससे एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण, लागत (डीजल) बचत, और कम लोडिंग समय लगेगा जिससे टर्नअराउंड समय कम हो जाता है और वैगन की उपलब्धता बढ़ जाती है।

15. एक पेड़ मां के नाम



14. वाणिज्यिक खनन

10वां और 9वें दौर का दूसरा प्रयास 21 जून, 2024 को क्रमशः 61 कोयला खानों और 6 कोयला खानों की पेशकश करते हुए शुरू किया गया था। इन दो दौर के तहत 14.1 एमटीपीए पीआरसी के साथ कुल 9 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।

वाणिज्यिक खनन के तहत अब तक कुल 113 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है जिसमें 257.60 मि.ट. पीए का पीआरसी है। एक बार पूरी तरह से चालू होने के बाद, इन खानों से 3.4 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार की क्षमता पैदा होगी और 38,600 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश आकर्षित होगा।

कोयला मंत्रालय ने "एक पेड़ माँ के नाम" पहल के तहत मिलेनियम पार्क में वृक्षारोपण अभियान चलाया। यह कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा अभियान का एक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य स्वच्छ और हरित वातावरण को बढ़ावा देना था। कोयला मंत्रालय में सचिव श्री वी. एल. कांता राव ने पौधरोपण अभियान का नेतृत्व किया और इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पौधरोपण किया। कोयला मंत्रालय के

अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके सामूहिक समर्पण को दर्शाती है। यह भागीदारी अपने खनन कार्यों में स्थायी प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है और देश के स्वच्छ और हरित मिशन का समर्थन करने में ऐसी पहलों के महत्व पर प्रकाश डालती है।



एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र ने एक पेड़ माँ के नाम-वृक्षारोपण अभियान के तहत खान में एक साथ 501 पौधों का रोपण किया।

16. अपशिष्ट से कला: -

"स्वच्छता ही सेवा" अभियान के दौरान, पर्यावरणीय स्थिरता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए "वेस्ट टू आर्ट" मूर्तिकला पहल का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अपशिष्ट पदार्थों, जैसे कि छोड़े गए प्लास्टिक, धातु और अन्य पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को कलात्मक मूर्तियों में बदलना शामिल था। इस पहल का उद्देश्य पुनर्चक्रण, अपशिष्ट में कमी और एक अभिनव और कलात्मक तरीके से सामग्री के पुनः उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मूर्तियां एक रचनात्मक अभिव्यक्ति और टिकाऊ प्रथाओं के मूल्य की याद दिलाती हैं, पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए जिम्मेदारी से कचरे के प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालती हैं।

